tion of the Government Servants' Conduct Rules by the employees of the Bihar State Government, then alone they can take any action if it is necessary. The Central Government has no jurisdiction over it.

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी बैनर्जी साहब ने मेरे मोटिव पर हमला किया। उसका मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि मेरे मोटिव में कुछ वहां के एम्प्लायीज को सैन्क्शोर करने की बात है।

श्री स० मो० बनर्जी : अनकांसशाली।

श्री विभूति मिश्र : तो एक दूसरे भगवान यह पैदा हो गए बैनर्जी साहब कि सब के मोटिव को जानने लगे कि किस का क्या मोटिव है। . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय यह जरा दूसरे ढंग से प्रश्न बनाना चाहिए। मतलब वही आ जाता है। प्रश्न जरा और ढंग से बनाना चाहिए था।

Mr. Speaker: At this rate, the Question Hour also will become something else. We would have no Question Hour. It is true that the elections are a Central subject. If the State Government employee misbehaves, the Central Government may bring it to the notice of the State Government, the elections are a Central subject. Whatever it may be, nothing more need be said on this now. I request the hon. Minister to answer the question.

Shri Sradhakar Supakar: Sir, I raise a point of order. If such frivolous points of order are raised by hon. Members on the other side, what is the remedy for us?

Mr. Speaker: Order order. The Minister may reply now.

बिहार में गत आम चुनावों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना

+

*901. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले आम चुनावों में बिहार सरकार के राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों ने सक्रिय रुप से भाग लिया था ;

(ख) यदि हां तो क्या ऐसा करना सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के विरुद्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां तो इस मामले मे क्या कार्यवाही की गई है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan): (a) The information is being collected from the State Government concerned.

(b) and (c). Do not arise.

Shri Shri Chand Goel: We can ask questions about other States also; not about Bihar only.

Mr. Speaker: Let the hon. Member put his first supplementary now.

श्री विभूति मिश्र : मंत्री जी ने जवाब दिया कि इस संबंध में इन्फार्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है। चुनाव फरवरी में गुजर गया और यह जूलाई का महीना है। इतने दिनों मे क्यों यह इन्फार्मेशन इकट्ठा नहीं किया गया और दूसरी बात स्टेट में एलेक्शन कमीशन की चुनाव की एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेट मे स्टेट के चुनाव के संबंध में एक कंट्रोलर रहता है। वह सारे स्टेट के एम्प्लायीज के द्वारा चुनाव का कार्य करता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास एलेक्शन कमीशन के अलावा और कोई एजेंसी है कि नहीं है। यदि है तो कौन सी है और यदि नहीं तो क्यों नहीं है ?

बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लायीज गजटेड और नान-गजटड ने पिछले आम चुनाव में खास तौर से चुनाव में भाग लिया और भाग ले कर के राजनीतिक पार्टी के जैसे काम किया। तो सरकार ने चुनाव की पद्धति को कायम रखने के लिए और चुनाव निरापद हों इस के लिए कौन सी कार्यवाही सोच रही है ?

Shri D. R. Chavan: The Election Commission is in charge of the elections. Direction and control of the elections is the responsibility of the Election Commission. It is an independent body, created under the Constitution under article 324. As a matter of fact, there is no other agency excepting the Election Commission, because you cannot go over the head of the Election Commission and make enquiries from the State Government. That is the first point.

The second point is this. The hon. Member asked why information has not been collected. It is not correct. As a matter of fact, the information was sought, and an interim reply was sent but the Election Commission was not satisfied with the interim reply, and therefore, again, a reference back has been made to the Chief Electoral Officer, who is in charge of the supervision of the entire election in Bihar State.

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष जी, चुनाव के संबंध में जो कुछ कार्यवाही होती है एलेक्शन कमीशन की तरफ से इस सदन में ला मिनिस्ट्री जवाबदेह है जवाब देती है। राजतंत्र के शास्त्र के अनुसार चन्द्रगुप्त का राज्य चलाने के लिए चाणक्य एक काम के पीछे 50 अपने गुप्तचरों को रखता था और सारी बातों को दरियाफ्त करता रहता था। तो मैं जानना चाहता हूं कि एलेक्शन में गड़बड़ी हुई....

श्री मधु लिमये : अरे, आप का इलाका चला जाता है और आप को पता नहीं चलता है और चाणक्य की बात करते हैं।

श्री विभूति मिश्र : आप से मैं ज्यादा जानता हूं।

श्री मधु लिमये : पूरा अक्साई-चीन चला गया, पता नहीं लगा।

श्री विभूति मिश्र : मेरी बात सुनिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ला-मिनिस्ट्री या सरकार इलैक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर निर्भर रहेगी। क्योंकि इलैक्शन कमीशन जिन के जरिये चुनाव कराता है वे अपनी खामियों को बताने के लिये कभी तैयार नहीं होंगे क्या सरकार इस के लिये कोई इन्डीपेन्डेन्ट जांच करायेगी ताकि इलैक्शन्ज में फेयरनेस आ सके ?

Shri D. R. Chavan: Just for the purpose of ensuring free and fair election, an independent body has been created by the framers of the Constitution. That is the body which is responsible for the conduct of elections. Naturally that body has got to act through the State agency—the Chief Electoral Officer and others. Therefore, though there may be any other machinery with the Government of India, we cannot go over the head of the Election Commission and make enquiries independent of it, because it is the channel through which we have to function.

Mr. Speaker: Shri Tiwary.

Shri Bibhuti Mishra: For having a fair and free election, what is the plan that the Government is thinking of?

Mr. Speaker: Shri Tiwary.

श्री क० ना० तिवारी : मिनिस्टर महोदय ने कहा है कि एक इन्टैरिम रिपोर्ट बिहार गवर्नमेंट से आई थी, उस से इलैक्शन कमीशन सैटिस्फाइड नहीं हुआ, इस लिये अब फरदर रिपोर्ट मांगी है। मैं यह

जाना चाहता हूं कि इन्टेरिम रिपोर्ट क्या थी और उस में कौन से प्वाइंट्स थे, जिन पर इलैक्शन कमीशन ने डिफर किया और जिन पर फरदर रिपोर्ट मांगी है ? यह रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है ?

Shri D. R. Chavan: A number of complaints were received by the Election Commission from certain candidates and other individuals. The interim reply that we have received is that there is no basis in the allegation that the gazetted and non-gazetted employees actively participated in the elections. This reply was received with which the Election Commission is not satisfied. (*Interruptions*). So, on the 27th a reference has been made to the Chief Electoral Officer to send a copy of all the enquiries he instituted into each of the complaints as early as possible.

Shri Dinkar Desai: May I know how many years Government will take to get the information?

Shri D. R. Chavan: I have already said that a reference has been made to the Bihar Government only recently. It is not as if the matter is pending for a number of years. The question is frivolous.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इलैक्शन कमीशन को बिहार के अधिकारियों से या बिहार के वर्तमान मुख्य मंत्री या दूसरे मंत्रियों से कोई शिकायत मिली है या अभी जो मुख्य मंत्री हैं या मंत्री मंडल के सदस्य हैं उन्होंने इलैक्शन कमीशन का ध्यान चुनाव से पहले चुनाव अधिकारियों द्वारा दखल देने की ओर दिलाया था, यदि दिलाया था तो क्या उसकी जांच हो रही है ?

Shri D. R. Chavan: I have no information on this.

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि बिहार के आम चुनाव निष्पक्ष ढंग से हों, इस के लिये उस समय की विधान सभा के तमाम विरोधी दलों ने यह मांग की थी कि उस वक्त का जो आतंकवादी मंत्री मंडल था उस आतंकवादी मंत्री मंडल को अपदस्थ किया जाय, उन के रहते हुए वहां पर निष्पक्ष आम चुनाव नहीं हो सकता है। क्या इसकी जानकारी मंत्री महोदय को है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उस वक्त के मुख्य मंत्री ने खुले आम सरकारी कर्मचारियों को यह कहा था, धमकी दी थी, कि तुम कांग्रेस दल को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी जगह जेलखाने में होगी और उन्होंने बहुत से लोगों को जेल में डाला था और बहुत सों पर मुकदमा चलाया था ?

Shri D. R. Chavan: I have no information on this point.

श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने विरोधी पार्टियों के . . .

Mr. Speaker: We will go to the next question.

श्री योगेन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल के जवाब का क्या हुआ ?

One-Day Poll

\+

*902. **Shrimati Tarkeshwari Sinha:**
Shri C. K. Bhattacharyya:

Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether during a recent meeting of the Chief Electoral Officers, the possibility of having one-day poll throughout the country was discussed;

(b) whether this scheme has been worked out; and

(c) if so, what has been the ultimate decision of Government in this matter?